अनिल क्षेत्रपाल न्यायधीश के सामने

बेलेव्यू सेंट्रल पार्क-II कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन - याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स सेंट्रल पार्क हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.- प्रतिवादी

सीआर नंबर 2020 का 1667

17 मार्च 2020

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996—एस. 8—व्यावसायिक न्यायालय अधिनियम, 2015-एस.11-वसूली के लिए सिविल मुकदमा-पक्षों को संदर्भित करना मध्यस्थता समझौते के मद्देनजर मध्यस्थता - आयोजित, यदि कोई पक्ष है यदि कोई व्यक्ति विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने में रुचि रखता है तो उसे मध्यस्थता करनी होगी अपना पक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से पहले तुरंत न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें विवाद के सार पर पहला बयान, ऐसा न होने पर कि कौन सा पक्ष आपत्ति कर रहा है यह माना जाएगा कि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है।

यह माना गया कि, 1996 अधिनियम की धारा 8 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह सही है स्पष्ट है कि यदि कोई पक्ष पार्टियों को संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण चाहता है मध्यस्थता, तो उसे आवेदन करना होगा लेकिन की तारीख से बाद में नहीं विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते हुए। अन्य में शब्द, धारा 8 तभी लागू की जा सकती है जब पक्ष न्यायिक में आवेदन करता है वह प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी मामले में कार्रवाई की जाती है एक मध्यस्थता समझौता लेकिन उसके प्रस्तुत करने की तारीख से बाद में नहीं विवाद के सार पर पहला बयान. का शाब्दिक अर्थ है धारा 8 का आशय यह है कि पक्ष को न्यायिक में आवेदन करना होगा प्राधिकारी को अपना पहला विवरण जमा करने की तारीख से पहले नहीं विवाद का सार. इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली हाई की डिवीजन बेंच कोर्ट ने व्याख्या की है कि इस तरह की आपत्ति में भी लिया जा सकता है हालाँकि, लिखित बयान या मुकदमे में काउंटर दाखिल करते समय, वह आई.पी.एस.ओ वास्तव में इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसी आपत्ति होने के बाद उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है सुनवाई के दौरान अंतिम बहस के चरण में इसे छोड़ दिया गया मुकदमा व्यावहारिक रूप से ख़त्म हो चुका है।

(पैरा 7)

आगे कहा गया कि, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के खिलाफ दिया गया है यह माना जाता है कि यदि कोई पक्ष विवाद को संदर्भित करने में रुचि रखता है मध्यस्थ को तुरंत न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना होगा,पदार्थ पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख से बाद में नहीं विवाद का, ऐसा न करने पर आपत्ति करने वाले पक्ष को माना जाएगा उसका हक माफ कर दिया है.

(पैरा 12)

मयंक जैन, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए

अनिल क्षेत्रपाल, न्यायधीश

(1) जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस न्यायालय को बुलाया गया है वह यह है कि क्या ए विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक खंड वाले समझौते का पक्ष की स्थिरता पर आपत्ति के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से लिखित बयान में सिविल सूट के संदर्भ के लिए प्रार्थना नहीं करता है मध्यस्थ न्यायाधिकरण में विवाद, क्या यह इसके लिए स्वीकार्य होगा सिविल मुकदमा होने पर सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करने वाला पक्ष क्या मुकदमे की समाप्ति के बाद अंतिम बहस के लिए तैयार है?

(2) प्रतिवादी ने विशेष वाणिज्यिक के समक्ष एक नागरिक मुकदमा दायर किया न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2018 को निश्चित वसूली हेतु डिक्री पारित करने हेतु मात्रा। नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता (मुकदमे में प्रतिवादी)। वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष) ने लिखित बयान दायर कर दावा किया कि वाणिज्यिक की धारा 11 के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है न्यायालय अधिनियम, 2015. आगे कहा गया कि धारा 13 के अनुसार सुविधा एवं प्रबंधन अनुबंध दिनांक 22.3.2017 को विवाद है मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, इसलिए, वर्तमान मुकदमा है कायम करने योग्य नहीं है। इसके बाद दिनांक 6.7.2019 को विद्वान की उपस्थिति में पक्षों के वकील, मुद्दों को तैयार किया गया और न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया संपूर्ण कार्यवाही का शेड्यूल. आदेश दिनांक 16.7.2019 पारित हुआ वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निकाला गया है: -

> "केस प्रबंधन की सुनवाई पर सुनवाई हुई। के आधार पर पार्टियों की दलीलों में निम्नलिखित मुद्दे रखे गए हैं स्थगन के लिए नीचे:-
>
> 1)क्या वादी वसूली का हकदार है रु.1,12,94,851/- जिसमें मूल राशि भी शामिल है रु.98,28,463/- और रु. 14,66,388/- ब्याज के रूप में गणना की गई 06.10.2018 तक 18% प्रति वर्ष? ओपीपी
> 2) क्या वर्तमान स्वरूप में मुकदमा चलने योग्य नहीं है? ओपीडी
> 3) क्या वादी अपने ही कृत्य से बाधित है और आचरण? ओपीडी
> 4) राहत.
>
> 2. मामले के अभिलेखों के अवलोकन एवं प्रकृति से इस मुकदमे में विवाद, पूरे कार्यक्रम का पालन की सहमति से कार्यवाही निम्नानुसार रखी गई है पक्ष/वकील:-
>
> i) दोनों पक्षों द्वारा गवाहों की सूची या पर दायर की जाएगी 31.7.2019 से पहले. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में पक्ष या पार्टियाँ गवाहों की सूची दाखिल करने में विफल रहती हैं दी गई समय सीमा में उन्हें अपना साक्ष्य लाना होगा स्वयं की जिम्मेदारी है और वे इसका उपयोग करने के हकदार नहीं होंगे न्यायालय की प्रक्रिया.
>
> ii) दोनों पक्षों द्वारा गवाहों द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र 31.7.2019 को या उससे पहले दायर किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि में यदि कोई भी पक्ष अपेक्षित हलफनामा दायर करने में विफल रहता है समय अवधि के भीतर ही पार्टियों द्वारा इसे दायर किया जा सकता है प्रति शपथपत्र, प्रति सुनवाई 1,000/- रुपये की लागत का भुगतान करना लागत केवल जिला विधिक सेवा के कोष में देय होगी अधिकार।

iii) यदि पार्टियां कोई विविध कदम उठाना चाहती हैं आवेदन, 31.7.2019 को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए।

iv) वादी और प्रतिवादी दोनों को लगभग एक ही अनुदान दिया जाता है प्रत्येक को अपने साक्ष्य के निष्कर्ष के लिए एक महीने का समय। साक्ष्य स्थानीय आयुक्त के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे।

वादी साक्ष्य के लिए अनुसूची निम्नानुसार निर्धारित की गई है: -

06.08.2019 : वादी साक्ष्य के लिए पहली तारीख।
14.08.2019 : वादी साक्ष्य हेतु द्वितीय तिथि
27.08.2019 : वादी साक्ष्य के निष्कर्ष हेतु

(वादी को शेष राशि लाने का भी अधिकार होगा साक्ष्य, यदि कोई हो, 31.8.2019 तक)

vi) प्रतिवादियों की गवाही के लिए कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है अंतर्गत:-

05.9.2019 : प्रतिवादियों की गवाही के लिए पहली तारीख।
12.9.2019 : प्रतिवादियों की गवाही के लिए दूसरी तारीख।
25.9.2019 : प्रतिवादियों के साक्ष्य के निष्कर्ष हेतु।

(प्रतिवादी को शेष लाने का भी अधिकार होगा साक्ष्य, यदि कोई हो, 30.9.2019 तक)

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि पार्टियों के निष्कर्ष के बाद लिखा गया है एक सप्ताह के भीतर सबमिशन दाखिल किया जाए और उसके बाद मुकदमा दायर किया जाए एक माह की अवधि में सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा 30.9.2019 से.

6. अब फाइल सबसे पहले 31.7.2019 को डाली जाएगी।

(3) इसके बाद वादी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रतिवादी ने भी इसके साक्ष्य प्रस्तुत किये। साक्ष्य के समापन के बाद, एक आवेदन किया गया था विवाद को संदर्भित करने के लिए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा 10.1.2020 को दायर किया गया मध्यस्थ न्यायाधिकरण को, जिसे विद्वानों ने खारिज कर दिया है वाणिज्यिक न्यायालय, इस आधार पर कि इस स्तर पर, यह नहीं होगा पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना उचित है।

(4) इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है लम्बाई और उनकी सक्षम सहायता से दायर दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि बहुत ही कम सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति का प्रथम अवसर, दृष्टि में विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण से निपटाने के लिए खंड का लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय उसे इस पर ध्यान देना चाहिए था और पार्टियों को मध्यस्थ के पास भेजना चाहिए था

विवाद के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण. उन्होंने आगे यह भी कहा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 के तहत अलग आवेदन 1996 (इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की आवश्यकता नहीं थी दायर किया. इसके समर्थन में, उन्होंने डिवीजन द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया शरद पी. जगतियानी बनाम एडलवाइस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ सिक्योरिटीज लिमिटेड 1 उन्होंने आगे माननीय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया सुप्रीम कोर्ट ने 'हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मैसर्स' मामले में पिंकसिटी मिडवे पेट्रोलियम्स 2 1996 की धारा 8 का विरोध करने के लिए अधिनियम अनिवार्य है और न्यायालय विवाद को संदर्भित करने के लिए बाध्य है मध्यस्थ. उन्होंने आगे माननीय के निर्णय पर भरोसा जताया सुप्रीम कोर्ट ने पी. आनंद गजपति राजू और अन्य बनाम पी.वी.जी राजू (मृत्यु) और अन्य 3 का तर्क है कि अपील के स्तर पर भी,मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

> “धारा 8. पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां वहां हो।” एक मध्यस्थता समझौता है.—
>
> (1) A एक न्यायिक प्राधिकरण जिसके समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है एक मामला जो मध्यस्थता समझौते का विषय है यदि कोई पक्ष ऐसा आवेदन करता है तो उसे अपना सबमिट करने से पहले आवेदन करना होगा विवाद के सार पर पहला बयान, देखें मध्यस्थता के पक्षकार.
>
> (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन नहीं होगा जब तक यह मूल के साथ न हो तब तक मनोरंजन किया जाता है मध्यस्थता समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति।
>
> (3) इसके बावजूद कि एक आवेदन किया गया है उपधारा (1) के तहत और यह मुद्दा पहले से लंबित है न्यायिक प्राधिकरण, एक मध्यस्थता शुरू की जा सकती है या जारी रखा और एक मध्यस्थ निर्णय दिया गया।

(6) इस न्यायालय ने विद्वान की दलील पर विचार किया है हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील को इसमें कोई तथ्य नहीं मिला। इस पर चरण, 1996 अधिनियम की धारा 8 को निकालना उचित होगा:

(7) अधिनियम 1996 की धारा 8 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलता है स्पष्ट है कि यदि कोई पक्ष पार्टियों को संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण चाहता है मध्यस्थता, तो उसे आवेदन करना होगा लेकिन की तारीख से बाद में नहीं विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते हुए। अन्य में शब्द, धारा 8 तभी लागू की जा सकती है जब पक्ष न्यायिक में आवेदन करता है वह प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी मामले में कार्रवाई की जाती है एक मध्यस्थता समझौता लेकिन उसके प्रस्तुत करने की तारीख से बाद में नहीं विवाद के सार पर पहला बयान. का शाब्दिक अर्थ है धारा 8 का आशय यह है कि पक्ष को न्यायिक में आवेदन करना होगा प्राधिकारी को अपना पहला विवरण जमा करने की तारीख से पहले नहीं विवाद का सार. इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली हाई की डिवीजन बेंच कोर्ट ने व्याख्या की है कि इस तरह की आपत्ति में भी लिया जा सकता है हालाँकि, लिखित बयान या मुकदमे में काउंटर दाखिल करते समय, वह आई.पी.एस.ओ वास्तव में इसका मतलब यह नहीं होगा कि ऐसी आपत्ति होने के बाद उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है सुनवाई के दौरान अंतिम बहस के चरण में इसे छोड़ दिया गया मुकदमा व्यावहारिक रूप से ख़त्म हो चुका है।

(8) इस मामले की जांच दूसरे नजरिये से भी की जा सकती है.1996 का अधिनियम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक नहीं लगाता है। अनुभाग 1996 अधिनियम का 8 जो एक न्यायिक प्राधिकार को अनिवार्य बनाता है जिसके समक्ष एक किसी मामले में कार्रवाई की जाती है, जो मध्यस्थता का विषय है समझौता, पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए यदि कोई पक्ष है मध्यस्थता समझौता लागू होता है, लेकिन इसकी तारीख के बाद नहीं अपना पहला वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए। इस प्रकार, एक पक्ष को विकल्प दिया जाता है इस संबंध में न्यायिक प्राधिकरण को आवेदन करें। न्यायालयों के पास है धारा 8 की व्याख्या इस प्रकार की गई कि यदि रखरखाव पर आपत्ति है समझौते में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति में मुकदमे का है उचित समय पर न्यायालय/न्यायिक प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया चरण, तो न्यायालय पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, यह पार्टी है जिसे चुनाव करना है और चुनना है कि वह क्या है चाहता है कि न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करे या वह ऐसा करना चाहता है न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही जारी रखें।

(9) इस मामले की जांच दूसरे एंगल से भी की जा सकती है. मध्यस्थता न्यायाधिकरण पार्टियों द्वारा एक समझौते के द्वारा चुना गया एक मंच है उनके विवाद का निपटारा हो रहा है। एक बार कोई पक्ष आपत्ति करने का अपना अधिकार छोड़ देता है सिविल मुकदमे की पोषणीयता के लिए और पहले दबाव नहीं डालता है न्यायिक प्राधिकरण पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं कर सकता है बाद में उपरोक्त आपत्ति लागू करने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि देखा गया उपरोक्त, वर्तमान मामले में लिखित बयान दाखिल करने के बाद प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जताई किसी ने भी मुकदमा कायम करते समय मुकदमे की विचारणीयता पर आपत्ति नहीं जताई सबूत पेश करते समय न तो मुद्दे उठाए और न ही आपत्ति जताई। वादी भी प्रतिवादियों ने पहले ही अपनी गवाही पूरी कर ली है। इसलिए, इस स्तर पर, न्यायिक अनुरोध करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 8 को लागू नहीं किया जा सकता है पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार। दिल्ली द्वारा निर्णय पारित किये गये याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उच्च न्यायालय का हवाला नहीं दिया जाएगा लागू है क्योंकि उपरोक्त मामले में लेने के बाद लिखित बयान में आपत्ति पर कोर्ट का ध्यान गया जब मुकदमा प्रारंभिक चरण में था और तुरंत वापस ले लिया गया डिवीजन बेंच ने कहा कि अलग से कोई आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

(10) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निर्णय। (सुप्रा) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी स्थिति की जांच कर रहा था जहां 1996 अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन दायर किया गया था लेकिन वही था इस आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया कि मुकदमे में शामिल विवाद के दायरे में नहीं आता है मध्यस्थता समझौता. उन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक प्राधिकार के पास रेफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है एक बार मध्यस्थता समझौता लाए जाने के बाद पार्टियों को मध्यस्थता के लिए लाया जाता है न्यायिक प्राधिकारी की सूचना. यह माना गया कि यह मध्यस्थ के लिए होगा न्यायाधिकरण यह तय करेगा कि विवाद इसके दायरे में आता है या नहीं मध्यस्थता समझौता या नहीं.

11) इसके अलावा, विद्वान वकील द्वारा भरोसा जताया गया याचिकाकर्ता पी. आनंद गजपति राजू (सुप्रा) द्वारा एक निर्णय पारित किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गलत धारणा है। को ध्यान से पढ़ने पर निर्णय से यह स्पष्ट है कि पहले अपील के लंबित रहने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पार्टियों ने मध्यस्थता में प्रवेश किया समझौता और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया अपने विवाद को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजें। उस संदर्भ में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1996 के

अधिनियम की धारा 8 को इस प्रकार लागू किया जा सकता है धारा 8 की भाषा अनुदेशात्मक है। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं होते मामला।

(12) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न शुरुआत में तैयार किए गए जवाब का जवाब याचिकाकर्ता के खिलाफ दिया गया है और इसे बरकरार रखा गया है कि यदि कोई पक्ष विवाद को मध्यस्थ के पास भेजने में रुचि रखता है न्यायालय का ध्यान तुरंत आकर्षित करना होगा, बाद में नहीं विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तिथि, ऐसा न करने पर आपत्ति करने वाले पक्ष को उसका अधिकार माफ कर दिया गया माना जाएगा सही।

(13) तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

ऋतंभरा ऋषि

अस्वीकरण -

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समज सके और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये निर्णय का अंगरेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन कार्यावयन

के उददेश्य के लिये उपयुक्त रहेगा ।

सुरेश पाल सन्धु